

परियोजनाओं की स्वीकृति से लेकर कार्यादेश तक सभी प्रक्रियाओं को स्ट्रीम लाइन करें- भजनलाल

राज उन्नति की बैठक में खाटू श्याम जी मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान करने के निर्देश दिए

जयपुर, 19 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पानी, बिजली, चिकित्सा, सड़क सहित, जनसुविधाओं से जुड़े किसी भी काम में प्रशासनिक शिथिलता के कारण देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में "राज उन्नति" की छठी बैठक में कहा कि आमजन को

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रीगंगानगर जिले में एक ही भूमि के दो पट्टे जारी किए जाने पर जन सुविधा की आरक्षित भूमि पर व्यवसायिक पट्टा देने के प्रकरण में यूआईटी सचिव सहित 6 कार्मिकों को निलंबित करने के निर्देश दिए।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज उन्नति की छठी बैठक में अधिकारियों दिशा-निर्देश दिए।

में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारी मौके पर जाकर मुआयना करें और शीघ्रता से काम पूरा करवाएं। उन्होंने कहा कि देखने में आया है कि बड़ी परियोजनाओं में स्वीकृतियां, भूमि अधिग्रहण, निविदा प्रक्रिया और कार्यादेश जारी करने में लम्बा समय लगता है। उन्होंने मुख्य सचिव को इन प्रक्रियाओं को स्ट्रीमलाइन कर परियोजनाओं में देरी न होने तक काम करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने श्रीगंगानगर जिले में एक ही भूमि के दो पट्टे जारी किए जाने पर, तथा जनसुविधा हेतु आरक्षित भूमि पर व्यवसायिक पट्टे जारी किए जाने के प्रकरण में यूआईटी सचिव सहित, इस

प्रकरण में संप्लित आधा दर्जन से अधिक कार्मिकों को निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की जिलेवार रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 7 विभागों की 8 प्रारम्भिक आरडीसी को निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज उन्नति की पूर्व बैठकों में मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना की प्रगति की जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि हर माह होने वाली राज उन्नति की बैठक में मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से सीधे संवाद कर प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं तथा समस्या का वास्तविक समय में समाधान किया जाता है।

को देखते हुए, जयपुर के लालकोठी क्षेत्र में प्रस्तावित कर्मयोगी भवन स्थापना की कार्ययोजना की समीक्षा की तथा आरएसआरडीसी को निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज उन्नति की पूर्व बैठकों में मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना की प्रगति की जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि हर माह होने वाली राज उन्नति की बैठक में मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से सीधे संवाद कर प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं तथा समस्या का वास्तविक समय में समाधान किया जाता है।

योजनाओं और विकास परियोजनाओं का निरन्तर लाभ मिलना चाहिए। निविदा प्रक्रिया में देरी या किसी भी अन्य कारण से इनमें रुकावट आई तो अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने सांगानेर में सीईटीपी के पर्मिग स्टेशन और पाइप-लाइन के काम

अमेरिका-ईरान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हुई। ईरान ने लेबनान में हिंसा और हमलों को रोकने की शर्त के उल्लंघन की ओर इशारा किया, जिसे समझौते को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक माना गया था।

इसके बाद, ईरान जिनेवा वार्ताओं से अलग हो गया, वार्ता में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति वेंस शुक्रवार को स्विट्जरलैंड जाने वाले थे। ईरान के हटने के बाद वेंस को अपना स्विट्जरलैंड दौरा रद्द करना पड़ा और स्थिति फिर से पहले जैसी अनिश्चित हो गई है।

इजरायल और हिज्बुल्लाह, दोनों ही ईरान और अमेरिका के बीच की वार्ता प्रक्रिया से स्वयं को बाहर महसूस कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता लागू नहीं हो पाया था। ईजरायल का मानना था कि उसे शामिल नहीं किया गया, जबकि हिज्बुल्लाह को लगा कि उसका समर्थक रहा ईरान उसके हितों को नजरअंदाज कर समझौता कर रहा है। वार्ता के बाधित होने से विषय और कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं और लोगों की खुशहाली पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। युद्ध और तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल की आपूर्ति रुक गई थी, जिससे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग 120 डॉलर प्रति बैरेल तक पहुंच गई थी।

भाऊत भी ईरान संकट से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ, क्योंकि तेल और खासकर एलएनजी (ससोई गैस) की आपूर्ति लगभग बंद हो गई थी। युद्ध शुरू होने के बाद ससोई गैस की कीमतें तेजी से बढ़ीं, जिससे भारतीय परिवारों

पर आर्थिक दबाव बढ़ गया। आज एक टैंकर भारत पहुंचा है, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते तेल लेकर आया है। शुक्रवार को 25 जहाज इस जलमार्ग से गुजरे, जो पहले की तुलना में बढ़ा हुआ है, जब लगभग कोई आवाजाही संभव नहीं थी। ईरान ने कहा है कि वह इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को मुफ्त समुद्री सेवाएं प्रदान करेगा।

अमेरिका-ईरान समझौते के अनुसार, समुद्री मार्ग पूरी तरह से खोला जाना था और ईरान बिना किसी शुल्क के जहाजों को गुजरने देगा। यह वही व्यवस्था थी जो युद्ध शुरू होने से पहले थी।

चौदह बिंदुओं वाले इस समझौते में ईरान की परमाणु कार्यक्रम में आगे न बढ़ाने की प्रतिबद्धता, नुकसान को भरपाई और ईरानी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 300 अरब डॉलर का पुनर्निर्माण कोष, और अमेरिका द्वारा सभी प्रतिबंध हटाने का प्रावधान शामिल था।

यह समझौता ईरान को कई रियायतें देता है, जिसमें सभी प्रतिबंधों का हटाना और वैश्विक बाजारों तक पहुंच बहाल होना शामिल है। लेकिन अब हिज्बुल्लाह की कार्रवाई के कारण ईरान इन लाभों को खोने की स्थिति में है।

दूसरी ओर, इजरायली सरकार पर दक्षिणपंथी समूहों का भारी दबाव है, जो इजरायली सैनिकों की मौत के लिए हिज्बुल्लाह को कठोर सजा देने की मांग कर रहे हैं।

दोनों पक्षों का रुख सख्त होने के कारण, शांति प्रक्रिया के बाधित होने की आशंका और बढ़ गई है।

काँकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन आज

नई दिल्ली, 19 जून। नोट परीक्षा में कथित पेपर लीक और उससे जुड़े विवादों के बीच काँकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखकर छात्र आत्महत्याओं के मामलों में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। पार्टी ने 20 जून से दिल्ली के जंतर-मंतर पर

पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री को छात्र आत्महत्याओं पर खुला पत्र लिखा।

प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि हाल के दिनों में परीक्षा संबंधी तनाव और कथित पेपर लीक की घटनाओं के कारण कई छात्रों ने आत्महत्या की है। उन्होंने छात्रों को कि एसे छात्रों के परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। पत्र में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मप्र प्रधान की जवाबदेही तय करने की मांग भी उठाई गई है। काँकरोच जनता पार्टी के अनुसार, कल यानी 20 जून से जंतर-मंतर पर छात्र और समर्थक एकत्र होंगे।

पार्टी का कहना है कि देशभर से छात्र इस आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं।

कांग्रेस के साथ विलय का सवाल ही नहीं- उद्धव ठाकरे

मुंबई, 19 जून। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के 60वें स्थापना दिवस पर विरोधियों को करारा जवाब दिया है। मुंबई में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस के साथ पार्टी के विलय की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उद्धव ठाकरे ने दो दृक शब्दों में कहा कि जब हमने 30 साल के गठबंधन के बाद भी भाजपा के साथ अपनी पार्टी का विलय नहीं किया, तो फिर कांग्रेस के साथ विलय करने का सवाल ही नहीं होता।

अपनी पार्टी के छह लोकसभा सांसदों की बगवत के बीच शिवसेना-कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे।

उद्धव ठाकरे ने स्थापना दिवस पर कहा कि अगर पार्टी को मुझ पर विश्वास नहीं है तो पद छोड़ दूंगा।

यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को बालुका होते हुए कहा कि चुनौतियों और हमलों के बावजूद मेरा संकल्प कमजोर नहीं पड़ा है, लेकिन अगर पार्टी को मुझ पर भरोसा नहीं है, तो मैं अपना पद छोड़ने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा, मैं किसी भी योग्य व्यक्ति को शिवसेना का

नीट री-एग्जाम अभ्यर्थियों के लिए एनटीए ने एडवायज़री जारी की

एडवायज़री में ड्रेस कोड के अलावा कौन सी वस्तुएं ले जा सकते हैं, कौन सी नहीं, यह भी बताया गया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 19 जून। नेशनल टैस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नीट यूजी 2026 के 21 जून को होने वाले री-एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक एडवायज़री जारी की है, जिसमें परीक्षा केन्द्रों पर पालन किए जाने वाले ड्रेस कोड, अनुमति प्राप्त वस्तुएं और सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी दी गई है। एजेंसी ने उम्मीदवारों से उम्मीदवारों की है कि वे परीक्षा के सुचारु और सुरक्षित संचालन के लिए सभी निर्देशों का पालन करें।

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए निम्न दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं- पानी की पारदर्शी बोतल परीक्षा हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति है। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड बारिश में भीगने या किसी अन्य नुकसान से बचाने के लिए पारदर्शी प्लास्टिक पाउच में ले जा सकते हैं। उम्मीदवार आस्था से जुड़े वस्त्र या प्रतीक पहन सकते हैं, जैसे धार्मिक प्रतीक, कलावा, पगड़ी, हिजाब आदि। लेकिन, इसके लिए उन्हें समय से पहले परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्ट करना होगा, ताकि उचित जांच (फ्रिस्किंग) की जा सके। बेहतर होगा कि हल्के कपड़े पहनें, लेकिन आवश्यकता होने पर उम्मीदवार फुल स्लीव कपड़े या ऊनी वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन उनकी अतिरिक्त सुरक्षा जांच होगी। इसी प्रकार, चप्पल

दिशा-निर्देशों के अनुसार, पारदर्शी पानी की बोतल ले जा सकते हैं, एडमिट कार्ड को प्लास्टिक के पाउच में रख सकते हैं, पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, इयर फोन, स्मार्ट वॉच, बड़े बैल्ट बकल, धातु के आभूषणों आदि पर रोक है।

इसके अलावा अभ्यर्थी चाहे तो धार्मिक चिन्ह कलावा, पगड़ी, हिजाब आदि पहन सकता है, पर इसके लिए उन्हें निर्धारित समय से पहले आना होगा ताकि उनकी तलाशी प्रक्रिया हो सके।

हाई हील के जूते-चप्पल भी पहने जा सकते हैं और पूरी बाजू के वस्त्र या गर्म कपड़ों की भी अनुमति है, पर इनकी भी विशेष तलाशी होगी।

और कम हील वाले जूते पहनना बेहतर है। लेकिन हाई हील जूते भी पहने जा सकते हैं, किन्तु इन उम्मीदवारों की अतिरिक्त जांच हो सकती है। एनटीए ने परीक्षा हॉल में इन वस्तुओं को ले जाने पर रोक लगाई है: मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्ल्यूटूथ डिवाइस, इयरफोन, किसी भी प्रकार के संचार उपकरण, धातु की वस्तुएं, बड़े बैल्ट बकल, भारी आभूषण तथा अन्य

राहुल अब मुस्कुराकर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) ?
तमिलनाडु में कांग्रेस को एक नया सहयोगी मिल गया है और कई दशकों बाद कांग्रेस राज्य की सत्ता का हिस्सा बनी है।

मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं हैं और अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें कांग्रेस के मुस्लिम, दलित और कमजोर वर्गों के वोटों की आवश्यकता है।

लालू यादव भी अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में हैं और उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को नेता के रूप में स्वीकार कर लिया है। पिछले एक वर्ष में हुए इन बदलावों ने विपक्ष के बीच राहुल गांधी की स्थिति और छवि को मजबूत करने का काम किया है।

शिक्षा क्षेत्र, नीट, सीबीएसई, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी के हालिया हमलों को नई पीढ़ी, यानी जनरेशन-ज़ैड का समर्थन मिल रहा है। यह वही युवा वर्ग है, जो उभरते हुए

भारत का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन वर्तमान परिस्थितियों से नाराज़ तथा निराश है।

कांग्रेस के अधिक से अधिक कार्यकर्ता और नेता राहुल गांधी को भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं दे रहे हैं और अब वे इसे मुस्कुराकर स्वीकार कर रहे हैं।

उन्होंने 2004 में राजनीति में प्रवेश किया, लोकसभा चुनाव लड़ा और सांसद बने। तब से अब तक उनकी राजनीतिक यात्रा लंबी, कठिन और उतार-चढ़ाव से भरी रही है, जिसमें उपलब्धियों से अधिक असफलताएं रही हैं। लेकिन आज उनके 56वें जन्मदिन के समारोह में वे जिस आत्मविश्वास और दृढ़ता से भरे दिखाई दिए, उससे स्पष्ट था कि पार्टी के भीतर और बाहर, दोनों जगह वे अब अपनी स्थिति को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हैं।

संभव है कि वे अगले एक-दो दिन में विदेश यात्रा पर चले जाएं, लेकिन पिछले वर्ष से वे अपना जन्मदिन कांग्रेस पार्टी के साथ ही मना रहे हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा की हर समस्या ताकत से हल नहीं होती- उपराष्ट्रपति वेंस अमेरिका-ईरान समझौते पर इजरायल की आलोचनाओं पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने तीखी प्रतिक्रिया दी

वाशिंगटन, 19 जून। पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच 108 दिनों तक चले युद्ध के बाद अमेरिका-ईरान परमाणु समझौता वार्ता को लेकर इजरायल की आलोचनाओं पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गुरुवार को प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा कि हर राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी समस्या को ताकत का इस्तेमाल कर हल नहीं किया जा सकता। तुर्क एकीकृत सैनिकों के अनुरूप, एक बड़ा वर्ग इस समझौते को लेकर बेहद

इंटरव्यू में अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि इजरायल में इस समझौते को लेकर जो घबराहट और विरोध देखने को मिल रहा है, वह काफी हद तक अविश्वास और गलतफहमियों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने लंबे समय से इजरायल का विश्वसनीय साझेदार होने का प्रमाण दिया है और यह मानना कि वाशिंगटन ने कोई खराब समझौता किया है, तथ्यों से मेल नहीं खाता।

जेडी वेंस ने कहा कि इजरायल की राजनीतिक व्यवस्था और जनता का एक बड़ा वर्ग इस समझौते को लेकर बेहद

तुर्किये की सरकारी संवाद एजेंसी को इंटरव्यू में जेडी वेंस ने कहा कि इजरायल में इस समझौते पर घबराहट और विरोध काफी हद तक अविश्वास व गलतफहमियों पर आधारित है।

संवेदनशील है। उन्होंने विशेष रूप से इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमर बें-गवीर और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच का उल्लेख करते हुए कहा कि जो नेता इस समझौते की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनके पास वैकल्पिक समाधान क्या हैं।

उन्होंने कहा, "आप 90 लाख लोगों का देश है। आप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हर समस्या को केवल लोगों को मारकर या ताकत का इस्तेमाल कर हल नहीं कर सकते।"

अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने दावा किया कि यह समझौता न केवल इजरायल

बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र और दुनिया के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। उनके अनुसार, इस प्रक्रिया ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफी हद तक कम किया है और तेहरान को ऐसी रियायतें देने की स्थिति में पहुंचाया है, जो कुछ महिने पहले तक असंभव लगती थी।

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान ऐसे समय में आया है जब इजरायल और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं जारी हैं।

स्टालिन ने भी राहुल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लिखा: "भारत के विचार, हमारे संविधान और संघवाद की रक्षा के लिए हमारा साझा संकल्प हमें मार्गदर्शन देता रहेगा-यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा की लड़ाई है, और हम इसे साथ मिलकर तब तक लड़ते रहेंगे, जब तक जीत नहीं मिलती।"

यह उतर राहुल गांधी की ओर से उस अलग हुए सहयोगी के लिए एक संधि संदेश (ऑलिव ब्रान्च) माना जा रहा है, खासकर उस स्थिति में, जब कांग्रेस ने तमिलनाडु और आकांक्षाओं के लिए काम करते रहेंगे।

कांग्रेस के इस कदम से नाराज डीएमके ने पार्टी से संबंध तोड़ लिए हैं और इंडिया गठबंधन से भी दूरी बना ली है। पार्टी ने इस महिने की शुरुआत में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में भी भाग नहीं लिया और लोकसभा अध्यक्ष को यह पत्र भी लिखा है कि उसे सदन में नई बैठक व्यवस्था चाहिए, क्योंकि वह कांग्रेस सांसदों के साथ बैठना नहीं चाहती।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेमित्र जोसेफ विजय ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामना दी और उन्हें "भाई" कहा। इससे स्टालिन द्वारा 2025 में राहुल के जन्मदिन पर दी गई शुभकामना याद आ गई।

विजय ने लिखा: "आप, जो हमारे महान राष्ट्र भारत के विकास, लोकतांत्रिक

मूल्यों की रक्षा और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए अपनी आवाज उठाते रहते हैं, मैं आपकी अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु, आपके सभी प्रयासों में सफलता और सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट सेवा की कामना करता हूँ।"

राहुल गांधी ने विजय को जवाब देते हुए लिखा: हम संविधान और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट हैं-और साथ मिलकर हम तमिलनाडु के लोगों के कल्याण, गरिमा चुनावों के बाद टीवीके के साथ जाने का निर्णय ले लिया है।

कांग्रेस के साथ उनके बदलते संबंधों को दिखाते हैं, वहीं राहुल गांधी के जवाब भी एक अलग कहानी कहते हैं। विजय को उन्होंने तमिलनाडु स्तर पर काम जारी रखने का आश्वासन दिया, जबकि स्टालिन को उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विचार की रक्षा के साझा संकल्प का संदेश दिया।

यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या डीएमके राहुल गांधी के "एकता" के आ आन को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार करेगी। डीएमके के पास लोकसभा में 22 सांसद हैं और वह विपक्षी राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति है। खासकर तृणमूल और यूडिआ के विघटन के बाद, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए डीएमके के समर्थन के बिना प्रमुख भाजपा विधेयकों

को रोकना कठिन होगा। आने वाले सप्ताह यह बताएंगे कि स्टालिन भाजपा की विपक्षी दलों को विभाजित करने के कुत्सित खेल को कैसे देखते हैं और क्या वे मोदी-शाह के साथ मिलकर अल्पकालिक राजनीतिक लाभ लेने के बजाय, दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाते हैं।

शासन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) को पहली बार जमानती वारंट जारी करते हुए 12 जून को तलब किया था, लेकिन कार्यालय बंद होने की वजह से वारंट की तामील नहीं हो सकी। ऐसे में अगली सुनवाई पर बेंच ने फिर से आईएस को जमानती वारंट जारी करते हुए 1 जुलाई को तलब किया है।

पिछली सुनवाई पर बेंच ने कहा कि हमने विभाग के शासन सचिव अंबरीश कुमार को सम्मन जारी करते हुए 8 जून को बेंच के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। सम्मन की तामील होने के बावजूद, शासन सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही अनुपस्थिति का कोई कारण बताया गया। यह न्यायिक आदेशों की अवहेलना है। ऐसे में शासन सचिव को जमानती वारंट जारी किए जाते हैं।

'राम मंदिर के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) भाजपा के लिए नुकसानदेह दिख रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि पार्टी के अपने नेताओं ने भी इस मुद्दे को उठाया है। विवाद तब और बढ़ गया, जब समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडेय ने दावा किया कि कम से कम 7 करोड़ रुपये की दान राशि का गबन किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अदालतों से इन आरोपों पर संज्ञान लेने की अपील की है, जबकि भाजपा के कुछ नेताओं ने भी इस विवाद को और हवादी है।

भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने हाल ही में दावा किया कि उन्हें दान राशि के कथित दुरुपयोग की जानकारी है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसका विवरण देने से इनकार कर दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ट्रस्ट के वित्तीय मामलों में अधिक पारदर्शिता की मांग की है।

उन्होंने दान, खर्च, संपत्तियों, बैंक खातों और भूमि लेन-देन का विवरण सार्वजनिक रूप से जारी करने की मांग करते हुए कहा कि मंदिर में दान देने वाले श्रद्धालुओं को यह जानने का अधिकार है कि उनकी भेंट का उपयोग कैसे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रबंधन व्यवस्था के दो मूल आधार, ईमानदारी और निगरानी होते हैं, लेकिन इस मामले में दोनों स्तरों पर विफलता दिखाई दी है। पूर्व नौकरशाह ने कहा कि इस पूरे मामले से उन्हें बहुत दुख हुआ है, विशेषकर इसलिए क्योंकि यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब राम मंदिर प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है।

जहाँ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि घन के गायब होने का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है, वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसी महिने उत्तर प्रदेश सरकार से विस्तृत और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इसके बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया।